गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 023
दि. 23.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

शिष्टाचार बनाम सियासी कटुता: अजय राय के बयान से यूपी की राजनीति में मचा घमासान

Uttar Pradesh की राजनीति एक बार फिर तीखी बयानबाजी और राजनीतिक मर्यादाओं को लेकर बड़े विवाद के केंद्र में आ गई है। Ajay Rai का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। वीडियो में अजय राय प्रधानमंत्री Narendra Modi के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद न केवल भाजपा नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल में आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है।

राजधानी Lucknow से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान लगातार सामने आ रहे हैं। भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का उदाहरण बता रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी तक औपचारिक और विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जिस तेजी से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं, उससे यह साफ हो गया कि यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक तूल पकड़ सकता है।

इस पूरे विवाद को और अधिक संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी। एक मई को एक कार्यक्रम के दौरान अजय राय की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बताया गया कि उनके ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हुआ और शरीर में सोडियम की कमी आ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस टिप्पणी की उस समय व्यापक सराहना हुई थी।

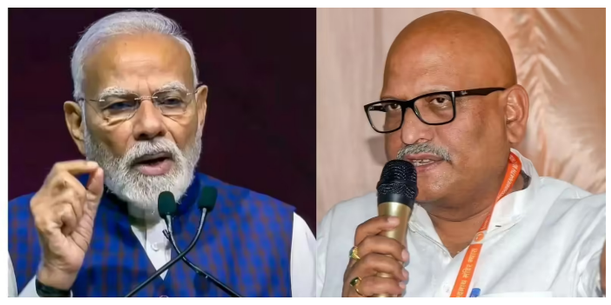

अब उसी संदर्भ को भाजपा लगातार सामने ला रही है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख Amit Malviya ने वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अजय राय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, लेकिन अब वही कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित मालवीय ने इसे "शिष्टाचार का जवाब अभद्रता से" करार देते हुए कांग्रेस की राजनीति के स्तर पर सवाल खड़े किए।

वायरल वीडियो में अजय राय एक कार में बैठे दिखाई दे रहे हैं। कार धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और आसपास खड़े कुछ लोगों से बातचीत के दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई देते हैं। वीडियो में वे एक वाक्य को दोहराते भी नजर आते हैं। हालांकि वीडियो की परिस्थितियों और पूरी बातचीत के संदर्भ को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विवाद तेज हो चुका है। भाजपा नेताओं ने इस मामले को केवल एक बयान नहीं बल्कि राजनीतिक मर्यादा और सार्वजनिक संवाद के स्तर से जोड़कर पेश किया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अजय राय पर निशाना साधते हुए उन्हें "कुसंस्कारी" बताया और कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष लगातार राजनीतिक संवाद का स्तर गिरा रहा है और व्यक्तिगत हमलों की राजनीति कर रहा है।

एनडीए के अन्य दलों के नेताओं ने भी इस बयान की आलोचना की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर हैं और राजनीतिक विरोध के बावजूद उनके प्रति सार्वजनिक भाषा में गरिमा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। भाजपा समर्थक सोशल मीडिया समूहों में भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में नेताओं की बयानबाजी कई बार राजनीतिक विमर्श को मुद्दों से हटाकर व्यक्तिगत हमलों की ओर मोड़ देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में नेताओं के हर शब्द और हर वीडियो का प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है। अब छोटी टिप्पणी भी कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाती है। Indian National Congress और Bharatiya Janata Party के बीच पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक संघर्ष लगातार तेज हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक दोनों दलों के नेता एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने मुद्दे को केवल राजनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे व्यक्तिगत शिष्टाचार और राजनीतिक संस्कारों से जोड़ दिया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अजय राय के स्वास्थ्य की चिंता जताने के बाद सामने आया यह विवाद भाजपा को नैतिक बढ़त देने का प्रयास भी बन सकता है। भाजपा लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक विरोध के बावजूद मानवीय संवेदनाएं रखते हैं, जबकि विपक्ष व्यक्तिगत कटुता की राजनीति करता है। हालांकि भारतीय राजनीति में तीखी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। चुनावी मौसम और राजनीतिक संघर्ष के दौरान नेताओं के विवादित बयान अक्सर सुर्खियां बनते रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में राजनीतिक भाषा के स्तर को लेकर चिंता लगातार बढ़ी है। कई बार न्यायपालिका और चुनाव आयोग तक नेताओं को मर्यादित भाषा इस्तेमाल करने की सलाह दे चुके हैं। इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारतीय राजनीति में वैचारिक विरोध अब व्यक्तिगत कटुता में बदलता जा रहा है। लोकतंत्र में आलोचना और विरोध आवश्यक माने जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब बड़े नेता आक्रामक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका असर समाज और राजनीतिक संस्कृति दोनों पर पड़ता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा गर्माया हुआ है। भाजपा इस मामले को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, जबकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन इतना तय है कि वायरल वीडियो ने एक बार फिर राजनीतिक संवाद की भाषा और मर्यादा को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।

कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ा सत्ता संघर्ष 35 विधायक दिल्ली कूच की तैयारी में

Karnataka की सियासत में कांग्रेस के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक Belur Gopal Krishna ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी के 30 से 35 विधायक जल्द ही दिल्ली जाकर कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। उनका उद्देश्य नेतृत्व पर दबाव बनाना है ताकि राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल किया जाए और नए विधायकों को मंत्री बनने का अवसर मिले। इस बयान ने कर्नाटक कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया है।

शिवमोगा में मीडिया से बातचीत करते हुए बेलुर गोपाल कृष्णा ने साफ कहा कि अब "करो या मरो" की स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के गठन को तीन साल हो चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों को अब तक सत्ता में भागीदारी का अवसर नहीं मिला है। ऐसे में पार्टी के भीतर असंतोष स्वाभाविक है। विधायक ने संकेत दिए कि यदि जल्द मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं हुआ, तो असंतुष्ट विधायक कड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो सकते हैं।

कांग्रेस विधायक के इस बयान को राज्य की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री Siddaramaiah और उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar के बीच नेतृत्व और सत्ता संतुलन को लेकर पहले से ही राजनीतिक चर्चाएं चलती रही हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा भी कांग्रेस के लिए नई चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। बेलुर गोपाल कृष्णा ने बताया कि पहले यह तय किया गया था कि केरल में नए मुख्यमंत्री के चयन के बाद दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। अब वहां नेतृत्व का फैसला हो चुका है, इसलिए अगले दो-तीन दिनों में बैठक कर अंतिम रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार केवल कुछ विधायक नहीं, बल्कि लगभग 35 विधायक दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। इससे साफ संकेत मिलता है कि असंतोष का दायरा पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा और लगभग 15 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। लेकिन असंतुष्ट विधायक इससे भी आगे जाकर 20 नए लोगों को मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान मंत्री तीन वर्षों से सत्ता और पद का लाभ उठा चुके हैं, इसलिए अब नए विधायकों को अवसर मिलना चाहिए।

विधायक ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई नियम नहीं है कि वही लोग लगातार मंत्री बने रहें। उनके अनुसार पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए सत्ता में संतुलित भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि असंतुष्ट विधायकों ने अब तक धैर्य रखा, सरकार के आधे कार्यकाल के बाद भी अतिरिक्त समय दिया, लेकिन यदि अब भी फेरबदल नहीं हुआ तो यह संदेश जाएगा कि पार्टी नेतृत्व केवल कुछ सीमित चेहरों को ही महत्व दे रहा है।

तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़, वीसीके और आईयूएमएल के कदम से बढ़ा सियासी तनाव

Tamil Nadu की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला है, जहां सत्ता समीकरणों में आए नए गठजोड़ ने राज्य की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। Dravida Munnetra Kazhagam (द्रमुक) ने अब अपने ही पुराने सहयोगी दलों Viduthalai Chiruthaigal Katchi (वीसीके) और Indian Union Muslim League (आईयूएमएल) पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। यह प्रतिक्रिया उस घटनाक्रम के बाद सामने आई है, जब इन दोनों दलों के नेताओं ने Tamilaga Vettri Kazhagam (टीवीके) सरकार में शामिल होकर मंत्री पद की शपथ ली।

चेन्नई में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। वीसीके नेता वन्नी अरसु, जो टिंडीवनम विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, और आईयूएमएल के ए एम शाहजहां, जो पापनासम से विधायक चुने गए थे, ने हाल ही में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री M. K. Stalin के साथ-साथ टीवीके नेतृत्व भी मौजूद बताया गया, जिससे यह संकेत मिला कि राज्य में सत्ता समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

नए मंत्रिमंडल में वन्नी अरसु को सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ए एम शाहजहां को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। इन नियुक्तियों को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह दोनों दल लंबे समय तक द्रमुक गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और अब उन्होंने एक नए राजनीतिक मंच के साथ सरकार में भागीदारी शुरू की है। द्रमुक की ओर से इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। पार्टी के उप महासचिव A. Raja ने इस राजनीतिक बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह "पड़ोसी की ओर झुकता नारियल का पेड़" जैसा है, जिसका अर्थ यह लगाया जा रहा है कि सहयोगी दल परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदल रहे हैं। यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। द्रमुक का आरोप है कि लंबे समय तक उनके साथ गठबंधन में रहे ये दल अब सत्ता के नए केंद्र की ओर झुक रहे हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि वीसीके ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उनका निर्णय किसी दबाव या लालच में नहीं लिया गया है, बल्कि राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया एक रणनीतिक फैसला है। वीसीके नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता में भागीदारी नहीं है, बल्कि राज्य में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता, खासकर राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति को रोकना भी है।

राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा, 10 राज्यों की 24 सीटों पर सियासी गणित तेज

देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। Election Commission of India ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों का आधिकारिक एलान कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार इन सीटों के लिए 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित राज्यों में राजनीतिक दलों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है और अब उम्मीदवारों के चयन से लेकर संख्या बल के आकलन तक बैठकों और रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है।

यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जून और जुलाई के बीच राज्यसभा के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली सदस्य सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनमें Mallikarjun Kharge, Digvijaya Singh और पूर्व प्रधानमंत्री H. D. Deve Gowda जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन नेताओं की विदाई के साथ राज्यसभा की राजनीतिक तस्वीर में नए समीकरण उभरने की संभावना भी बढ़ गई है।

चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार जिन राज्यों में राज्यसभा चुनाव होंगे उनमें Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand, Rajasthan, Karnataka, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh और Mizoram शामिल हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में चार-चार सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटों पर, झारखंड में दो सीटों पर तथा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सीट पर मतदान कराया जाएगा।

राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि संबंधित राज्यों के निर्वाचित विधायक करते हैं। इसलिए इन चुनावों में राजनीतिक दलों की वास्तविक ताकत और गठबंधन की स्थिति बेहद अहम हो जाती है। कई बार राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग और रणनीतिक समर्थन के कारण अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद सभी दल अपने विधायकों को एकजुट रखने और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर गंभीर मंथन में जुट गए हैं।

इस बार का चुनाव कई राज्यों में राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन सकता है। विशेष रूप से गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। वहीं झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन चुनावों के नतीजे आगामी राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी दे सकते हैं।

राज्यसभा को संसद का उच्च सदन माना जाता है और यहां की सदस्यता राष्ट्रीय राजनीति में विशेष महत्व रखती है। कई वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव न लड़कर राज्यसभा के माध्यम से संसद में पहुंचते हैं। यही कारण है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन केवल संख्या बल के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर भी किया जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कार्यकाल समाप्त होना विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी नेतृत्व को अब यह तय करना होगा कि उन्हें दोबारा किस राज्य से राज्यसभा भेजा जाए। इसी प्रकार दिग्विजय सिंह और एचडी देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ नेताओं की सीटों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। कई राज्यों में नए चेहरों को अवसर देने की संभावना भी जताई जा रही है।

राजस्थान से जिन नेताओं की सीटें खाली हो रही हैं उनमें Rajendra Gehlot, Neeraj Dangi और Ravneet Singh के नाम शामिल हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के भीतर रणनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजस्थान में विधानसभा की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यहां मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा।

चुनाव आयोग ने इस बार मतदान प्रक्रिया को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंगनी रंग का विशेष स्केच पेन ही इस्तेमाल किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग करने पर मत अमान्य माना जा सकता है। आयोग ने यह कदम मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। राज्यसभा चुनाव आम चुनावों की तरह जनसभाओं और बड़े प्रचार अभियानों वाले नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इनका महत्व बेहद बड़ा होता है। संसद के उच्च सदन में संख्या संतुलन सरकार की विधायी क्षमता को प्रभावित करता है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में राज्यसभा की भूमिका निर्णायक बन जाती है। यही कारण है कि केंद्र की राजनीति में मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए सभी दल राज्यसभा सीटों को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार राज्यसभा चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं होंगे, बल्कि यह आने वाले समय की राष्ट्रीय राजनीति का संकेत भी देंगे। जिन राज्यों में गठबंधन सरकारें हैं या जहां राजनीतिक समीकरण बेहद करीबी हैं, वहां एक-एक वोट की अहमियत बढ़ जाएगी।

संपादकीय

लू से हलकान जिंदगी

हाल के दिनों में आसमान से बरसती आग से देश में जन-जीवन बुरी तरह झुलस रहा है। रोज तापमान बढ़ने के नये रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। ये असहनीय तापमान केवल स्वास्थ्य की चुनौती मात्र नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संकट भी है। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। स्कूल-कालेज तो लू के दौरान बंद किए जा सकते हैं, सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को तो तपती दोपहरी व लू के बीच काम करने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल, लू की मार जहां शारीरिक है, वहीं आर्थिक भी। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की आजीविका और श्रम उत्पादकता पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संकट को हाल के दिनों में हुई ईंधन की कीमतों की वृद्धि और महंगाई ने और बढ़ा दिया है। लोगों को सीमित संसाधनों में जीवन यापन को मजबूर होना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे घातक प्रभाव उस तबके को सहन करना पड़ता है जो 'रोज कुंआ खोदकर पानी पीने' को बाध्य है। एक दिन की कमाई से ही रात को उसके घर का चूल्हा जलता है। लू के निशाने पर वे अनौपचारिक श्रमिक हैं जो भारतीय आर्थिकी की रीढ़ है। सही मायनों में लू के खिलाफ लड़ाई को अब केवल एक मौसमी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या ही नहीं माना जा सकता है। धीरे-धीरे यह एक गंभीर आर्थिक चुनौती भी बनी है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बाबत चेताते रहे हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया था कि लू से उपजे हालात से भारत को सौ अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।

इससे पहले वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि भारत का तीन-चौथाई श्रमिक वर्ग लू से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर है। अनुमान है कि लू के तनाव के कारण होने वाली विश्वव्यापी नौकरियों की कमी में भारत की हिस्सेदारी आधी हो सकती है। दरअसल, भारत में सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में निर्माण श्रमिक, खेतिहर श्रमिक, किसान, स्ट्रीट वेंडर और डिलीवरी एजेंट शामिल हैं। हालांकि, समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्य समय का पुनर्निधारण, छायादार विश्राम क्षेत्र बनाने, जलपान सुविधा, सुरक्षात्मक कपड़े और स्वास्थ्य निगरानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है,लेकिन फिर भी संकट के दायरे को देखते हुए ये उपाय नाकाफी हैं। देखा जाए तो फिलहाल भारत में गर्मी के संकट से मुकाबले के लिये बनायी गई योजनाएं काफी हद तक अस्थायी रूप से राहत देने वाली हैं। वक्त की मांग है कि भीषण गर्मी वाले महीनों के लिये तत्काल व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए। ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो लू चलने के दौरान सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करे। इस साल के आरंभ में वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि भीषण गर्मी के दौरान चलने वाली लू को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया जाए। निस्संदेह, इस वर्गीकरण से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलने वाले धन का उपयोग लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने में मदद देगा। इसके अलावा लू के दौरान कई अन्य नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आते हैं। मसलन इस समय बिजली व पानी की खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। इससे निबटने के लिये मजबूत और सक्रिय तंत्र विकसित करने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से देश के नीति-निर्माताओं और अन्य हितधारकों के सामने इस संकट से मुकाबले के लिये स्पष्ट विकल्प मौजूद हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि समय रहते निर्णायक रूप से अनुकूलन का तंत्र विकसित करें। यदि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में अधिक मानवीय क्षति व आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

राजनीति सनातन विरोध की बजाय आममुद्दों पर केंद्रित हो

> “ यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है।

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसा विमर्श लगातार उभर रहा है, जिसने राजनीतिक बहस को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मूल प्रश्नों से हटाकर धार्मिक पहचान और आस्था के इर्द-गिर्द खड़ा कर दिया है। यह विमर्श है-सनातन समर्थन बनाम सनातन विरोध। आज देश में एक ओर सनातन संस्कृति को भारतीय जीवन का शाश्वत आधार मानने वाली शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर कुछ राजनीतिक वक्तव्य और प्रवृत्तियां ऐसी दिखती हैं जिन्हें जनमानस सनातन विरोध के रूप में देखता है। प्रश्न यह नहीं कि किसी विचारधारा से सहमति या असहमति क्यों है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या राजनीति का केंद्र धर्म होना चाहिए या जनजीवन के वास्तविक मुद्दे? भारत का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष संविधान पर आधारित है, जहां राज्य का कार्य किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजनीतिक दलों का दायित्व भी यही होना चाहिए कि वे जनता की समस्याओं, विकास और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक विमर्श राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है।सनातन केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना, जीवन-दर्शन और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। “सत्यं वद, धर्मं चर”, “वसुधैव कुटुम्बकम्”, “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जैसे सूत्र इसी सनातन दृष्टि के अंग हैं। इसलिए जब कोई राजनीतिक वक्तव्य सनातन को लेकर अपमानजनक या आक्रामक भाषा का उपयोग करता है, तो उसका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। तमिलनाडु में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने वाला वक्तव्य इसी कारण व्यापक विवाद का कारण बना। विपक्ष के अनेक दलों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत जैसे देश में करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला कथन राजनीतिक रूप से भी असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। यहां यह समझना आवश्यक है कि द्रविड़ आंदोलन की अपनी

ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। उसका मूल संघर्ष सामाजिक विषमताओं और जातीय वर्चस्व के विरुद्ध था। लेकिन जब सामाजिक सुधार का विमर्श पूरे धर्म या संस्कृति के विरोध जैसा प्रतीत होने लगे, तब वह जनस्वीकृति खो देता है।

यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। स्वयं भारतीय दर्शन में भी संवाद, बहस और आत्मचिंतन की परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दयानंद और गांधी-सभी ने समाज की विसंगतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने समाज को तोड़ने नहीं, सुधारने का मार्ग चुना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक भाषा संतुलन खो देती है। जब आलोचना सुधार की जगह अस्वीकार की भाषा बन जाती है, तब वह समाज में ध्रुवीकरण को जन्म देती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं कही जा सकती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विमर्श अधिक प्रभावी होकर उभरा है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान जैसे विषयों ने एक बड़े वर्ग में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिला। दूसरी ओर विपक्षी दल इस बदलते राजनीतिक मानस को समझने में कई बार असहज दिखाई दिए। कहीं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आस्था के बीच संतुलन बनाने में चूक की, तो कहीं उनके कुछ नेताओं के बयान उन्हें कठिन स्थिति में ले आए। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी राजनीति में यह देखा गया कि केवल जातीय समीकरण या पारंपरिक वोट बैंक अब पर्याप्त नहीं हैं। जनता सांस्कृतिक पहचान, विकास और राष्ट्रीय विमर्श को भी महत्व देने लगी है। ऐसे में यदि कोई दल हिंदू आस्था के प्रति असंवेदनशील दिखता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे विमर्श का दूसरा पक्ष भी है। क्या राजनीति का उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान के आधार पर समर्थन जुटाना होना चाहिए? क्या देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि संकट, आर्थिक असमानता और सामाजिक विघटन जैसे प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए? यह चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धर्म, विशेषकर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमूक आदि विपक्षी दलों एवं उनके कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को व्यापक जनसमुदाय ने सनातन पर आक्षेप या हिंदू भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता के रूप में देखा, जिसके राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दिए। किंतु इस विषय को केवल “हिंदू विरोध” बनाम “राजनीतिक विरोध” के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राष्ट्र है, जहां किसी भी राजनीतिक दल को सरकार, नीतियों या नेतृत्व का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यदि वह विरोध आस्था, संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से टकराता हुआ प्रतीत हो, तो उसका राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई दलों के लिए यह धारणा चुनौती बनी कि वे सत्ता-विरोध की राजनीति करते-करते सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं से दूर हो गए हैं। भारत में सनातन केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन, परंपरा, संस्कृति, सहिष्णुता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति असावधान भाषा या नकारात्मक संकेत जनमानस में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करते रहे हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यह भी अपेक्षा करती है कि राजनीतिक विमर्श व्यक्तियों, नीतियों और शासन के मुद्दों पर केंद्रित रहे, न कि धार्मिक ध्रूवीकरण पर। राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि वे मतभेद रखें, आलोचना करें, लेकिन भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक संवेदनशीलता और आस्था के सम्मान का संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जनता अंततः उसी नेतृत्व को स्वीकार करती है जो उसकी भावनाओं, परंपराओं और राष्ट्रीय मानस को समझने का प्रयास करता है।

भारत की राजनीति को “धर्म बनाम धर्म” की लड़ाई से ऊपर उठकर “जन बनाम जनसमस्या” के विमर्श की ओर बढ़ना होगा। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता मंदिर भी चाहती है और रोजगार भी, आस्था भी चाहती है और अवसर भी, संस्कृति भी चाहती है और आधुनिकता भी। केवल धार्मिक धुरवीकरण किसी राष्ट्र की स्थायी प्रगति का आधार नहीं बन सकता। आज आवश्यकता है कि राजनीतिक दल सनातन विरोध या हिंदू विरोध जैसे आरोप-प्रत्यारोपों की राजनीति से बाहर निकलें। यदि किसी परंपरा में सुधार की बात करनी है, तो वह सम्मानजनक भाषा और रचनात्मक दृष्टि से हो। सामाजिक न्याय का अर्थ सांस्कृतिक अस्वीकार नहीं होना चाहिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ अन्य दृष्टियों का निषेध भी नहीं होना चाहिए। भारतीय सभ्यता की शक्ति उसकी विविधता और सहिष्णुता रही है। यहां शंकराचार्य भी हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, कबीर भी हैं, वेद भी हैं और संविधान भी। भारत ने सदैव संवाद को संघर्ष से ऊपर रखा है। इसलिए राजनीति का भी दायित्व है कि वह समाज को जोड़ने वाली भाषा बोले। आज जब विश्व संघर्षों, सांस्कृतिक तनावों और पहचान की राजनीति से जूझ रहा है, तब भारत के पास “वसुधैव कुटुम्बकम्” का संदेश है। यही सनातन का वास्तविक स्वरूप भी है-समावेश, करुणा और सहअस्तित्व। राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना होगा कि वे जनता को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं-धार्मिक टकराव की ओर या राष्ट्रीय निर्माण की ओर? यदि राजनीति केवल आस्था के विवादों में उलझी रही, तो जनजीवन के वास्तविक प्रश्न पीछे छूट जाएंगे। लेकिन यदि राजनीति संस्कृति का सम्मान करते हुए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता को केंद्र बनाएगी, तो भारत एक संतुलित और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। सनातन का अर्थ शाश्वत है, और शाश्वत वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। इसलिए किसी भी प्रकार का अंध-विरोध या अंध-समर्थन समाधान नहीं हो सकता। आवश्यकता है विवेकपूर्ण दृष्टि, संतुलित राजनीति और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की। भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है कि वह आस्था का सम्मान करे, लेकिन राजनीति को जनहित का माध्यम बनाए। तभी लोकतंत्र भी मजबूत होगा और समाज भी समरस बनेगा।

प्रेरणा

वचन की कीमत

मानव जीवन में शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे विश्वास की नींव होते हैं। एक व्यक्ति का चरित्र उसके ज्ञान, धन या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसके दिए हुए वचनों से पहचाना जाता है। जिसने अपने शब्दों का सम्मान करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा धर्म सीख लिया। मित्रता भी केवल साथ बैठने, हंसने-बोलने या सुख-दुख बांटने का नाम नहीं है; सच्ची मित्रता वह है जिसमें एक-दूसरे के सम्मान, भावनाओं और विश्वास का मूल्य समझा जाए। संसार में अनेक लोग बड़े पद और महान उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार से लोगों के हृदय में स्थायी स्थान बना पाते हैं। महान वैज्ञानिक Albert Einstein ऐसे ही व्यक्तित्व थे, जिनकी महानता केवल विज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके भीतर मानवीय संवेदनाओं और वचन-पालन का अद्भुत गुण भी था।

आइंस्टीन का जीवन अत्यंत व्यस्तताओं से भरा हुआ था। दुनिया भर के विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक संस्थान और बड़े-बड़े मंच उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी प्रतिभा ने उन्हें विश्व का सबसे सम्मानित वैज्ञानिक बना दिया था। लेकिन इतनी प्रसिद्धि और व्यस्तता के बावजूद उनके भीतर एक सरल, विनम्र और संवेदनशील मनुष्य जीवित था। उनकी मित्रता प्रसिद्ध संगीतकार Leopold Godowsky के साथ अत्यंत गहरी थी। दोनों के बीच केवल परिचय नहीं, बल्कि आत्मीयता का संबंध था। वे एक-दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करते थे और मित्रता को केवल औपचारिकता नहीं मानते थे।

एक दिन गोदोव्सिकी ने मुस्कराते हुए आइंस्टीन से कहा कि उनका नाई उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। वह नाई आइंस्टीन को केवल एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखता था। उसके लिए आइंस्टीन किसी चमत्कार से कम नहीं थे। गोदोव्सिकी ने जब यह बात कही तो आइंस्टीन ने सहज भाव से उत्तर दिया कि वे अभी अत्यंत व्यस्त हैं, अन्यथा इसी समय चल पड़ते। उन्होंने नाई का पता अपनी जेब में रख लिया और कहा कि अवसर मिलते ही उससे अवश्य मिलेंगे।

यह एक सामान्य-सी घटना प्रतीत होती है। अधिकांश लोग ऐसी बातों को औपचारिकता समझकर भूल जाते हैं। कई बार हम भी दूसरों से सहजता में कह देते हैं कि कभी मिलेंगे, कभी आएंगे, या किसी दिन बात करेंगे, लेकिन समय बीतने के साथ वे शब्द स्मृति से मिट जाते हैं। परंतु महान व्यक्तित्वों की पहचान यही होती है कि वे अपने छोटे-से-छोटे वचन को भी हल्के में नहीं लेते। आइंस्टीन ने भी उस छोटी-सी बात को अपने मन में संजोकर रखा। दिन बीतते गए। महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। आइंस्टीन की व्यस्तताएं बढ़ती रहीं। उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों में जाना पड़ता था। अनेक वैज्ञानिक चर्चाएं, शोध और सभाएं उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। न्यूयॉर्क जाने का अवसर उन्हें लंबे समय तक नहीं मिला। लोग उन्हें अक्सर “भुलक्कड़ वैज्ञानिक” कहा करते थे, क्योंकि वे कई बार दैनिक जीवन की छोटी बातों को भूल जाया करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस व्यक्ति को दुनिया भुलक्कड़ मानती थी, उसने एक साधारण नाई से मिलने का अपना वादा नहीं भुलाया। समय का चक्र घूमता रहा। एक दिन आइंस्टीन को दुखद समाचार मिला कि उनके प्रिय मित्र गोदोव्सिकी अब इस संसार में नहीं रहे। यह समाचार उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। मित्र का वियोग किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के हृदय को तोड़ देता है। आइंस्टीन तुरंत न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने गोदोव्सिकी के परिवार को सांत्वना दी और अपने मित्र के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। यह स्वाभाविक था कि उस दुखद वातावरण में वे अपने मित्र की यादों में डूबे रहते। लेकिन उसी समय उन्हें वर्षों पहले किया गया अपना वचन भी याद आया। सांत्वना देने के बाद उन्होंने जो पहला कार्य किया, वह उस नाई से मिलने का था। यह केवल एक मुलाकात नहीं थी; यह वचन के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण था। उन्होंने उस पुराने पते को संभालकर रखा था। वे सीधे उस छोटी-सी दुकान पर पहुंचे, जहां शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि संसार का सबसे महान वैज्ञानिक कभी आएगा। उधर वह नाई वर्षों पहले की उस बात को लगभग भूल चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी हस्ती वास्तव में उससे मिलने आएगी। उसके लिए वह केवल एक भावनात्मक इच्छा थी, जो समय के साथ धुंधली पड़ चुकी थी। वह अपनी साधारण-सी दुकान में रोज की तरह काम कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और सामने आइंस्टीन खड़े दिखाई दिए। क्षणभर के लिए वह स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। संसार भर में जिनका नाम सम्मान से लिया जाता था, वे स्वयं उसके सामने खड़े थे। उसकी आंखें खुशी और भावुकता से भर उठीं। उसका गला रुंध गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। केवल एकटक आइंस्टीन को देखता रहा। उस क्षण वह केवल एक नाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी भावनाओं का सम्मान किया गया था। आइंस्टीन की महानता इसी घटना में छिपी है। महानता केवल असाधारण बुद्धि से नहीं आती, बल्कि छोटे लोगों के छोटे भावों को समझने से आती है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक साधारण नाई से मिलना उनके लिए महत्वहीन है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इतने वर्षों बाद उस वादे का क्या मूल्य रह गया होगा। उनके लिए शब्द का मूल्य समय से बड़ा था। वे जानते थे कि मनुष्य की सच्ची पहचान उसके व्यवहार से होती है। आज के समय में जब लोग संबंधों को स्वार्थ की दृष्टि से देखने लगे हैं, यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। हम अक्सर बड़े-बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन अपने छोटे वचनों को निभाना भूल जाते हैं। धीरे-धीरे यही भूल विश्वास को कमजोर कर देती है। मित्रता, परिवार और समाज की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, और विश्वास तभी बनता है जब शब्द और कर्म एक समान हों। वचन निभाने वाला व्यक्ति भले ही धनवान न हो, लेकिन वह लोगों के हृदय में अमूल्य स्थान बना लेता है। उसका कहा हुआ शब्द लोगों को सुरक्षा और भरोसा देता है। ऐसे लोग कम होते हैं, पर वही समाज में वास्तविक सम्मान पाते हैं। आइंस्टीन ने विज्ञान से दुनिया को ज्ञान दिया, लेकिन अपने व्यवहार से यह भी सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है।

यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। कभी-कभी किसी साधारण व्यक्ति की छोटी-सी इच्छा भी उसके लिए संसार की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। यदि हम अपने व्यवहार से किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, तो वही मानवता का सबसे सुंदर रूप है।

नई वैश्विक शक्ति की धुरी बनता चीन

चीन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 25वीं यात्रा के लिए 'रेड कार्पेट' बिछाया है। यह राष्ट्राध्यक्षों के बीच कूटनीति की उस आवृत्ति को रेखांकित करता है, जो अमेरिका के साथ उसके संबंधों से कहीं ज़्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के कुछ ही दिनों बाद इस यात्रा का मुख्य मकसद कुछ जोखिमों को संभालना था। इस मुलाक़ात में दोनों नेताओं ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, और आपसी सहयोग को और गहरा करने का संकल्प लिया। ट्रंप के बाद पुतिन का आना अंतर्राष्ट्रीय राजनय के नुक्ते-नज़र से चीन की दो बड़ी ताकतों के साथ संबंधों को संभालने की क्षमता को उजागर किया है। क्या पुतिन और ट्रंप की यात्राएं चीन के साथ 'त्रिपक्षीय समन्वय' का रास्ता खोल सकती हैं? लेकिन सवाल है, भारत ऐसी गठजोड़ से क्यों दूर होता चला गया है?

पिछले हफ़्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे थे। उनका मकसद वैसी ही ज़बरदस्त व्यापारिक डील्स पक्की करना था, जिनकी वकालत उन्होंने नौ साल पहले की थी—इन डील्स में सोयाबीन से लेकर विमान और ऊर्जा तक, सब कुछ शामिल था। पुतिन भी चीन में एक 'गंभीर' क़िस्म की नई ऊर्जा डील के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। बुधवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान में, दोनों देशों ने अमेरिका पर आरोप लगाया, कि वह अपनी 'गोल्डन डोम' परियोजना के ज़रिए 'रणनीतिक स्थिरता के लिए एक स्पष्ट ख़तरा' पैदा कर रहा है। 'गोल्डन डोम' अमेरिका की एक महत्वाकांक्षी और बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे अमेरिकी क्षेत्र को बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज़ मिसाइलों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इन सालों में, उनके आपसी तालमेल की पहचान सिर्फ़ शिखर सम्मेलनों और राजकीय दौरों से ही नहीं, बल्कि खाने-पीने, जन्मदिन मनाने, खेल आयोजनों, नाव की सवारी और झील के किनारे चाय पीने जैसे बेहद निजी रिवाजों की बढ़ती हुई सूची से भी बनी है। बड़ी सावधानी से बनाई गई दोस्ती मंगल और बुध को फिर से सुर्खियों में आई। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। पेइचिंग, मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच रिश्ते और भी ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं, जबकि ईरान के साथ अमेरिका-इस्राइल युद्ध को खत्म करने की बातचीत अभी भी रुकी हुई है, और यूक्रेन में रूस का संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है।

शी और पुतिन के बीच यह प्रगाढ़ सम्बन्ध रातों-रात नहीं बने। इस भरोसे को जीतने में काफी वक्त लगा है। 2013 में आधिकारिक तौर पर पद संभालने के बाद से, शी पुतिन से 40 से ज़्यादा बार मिल चुके हैं, जो पश्चिमी नेताओं के साथ उनकी मुलाक़ातों से कहीं ज़्यादा है। जब अक्तूबर, 2013 को बाली में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन पुतिन के 61वें जन्मदिन के साथ पड़ा, तो शी ने उन्हें एक केक दिया, दोनों नेताओं ने सॉसेज और वोडका के साथ मिलकर जश्न मनाया। जून, 2018 में चीन की पुतिन की राजकीय यात्रा की एक खास बात यह थी कि रूसी नेता ने थियानचिन के मशहूर 'चियान पिंग कुओज़ी' (तले हुए आटे की डंडियों में लिपटे पैनकेक) बनाने में अपना हाथ आज़माया, जिसे उन्होंने एक दावत के दौरान अपने मेज़बान को परोसा। लगभग तीन महीने बाद, सितंबर 2018 में, दोनों नेताओं ने एक बार फिर अपने खाना पकाने के हुनर का प्रदर्शन किया– इस बार रूस में। उन्होंने कुछ पारंपरिक रूसी पैनकेक बनाए, जिन्हें 'ब्लिनी' कहा जाता है; उन्होंने इन पैनकेक के ऊपर 'कैवियार' (मछली के अंडे) डाले और साथ में 'वोदका शॉट्स' का भी आनंद लिया। पुतिन पर जिस पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, वह अलग-थलग पड़ गए दिखते हैं, और उन पर पश्चिमी देशों द्वारा युद्ध अपराधों के आरोप लगाए जा रहे हैं।

यह पहली बार ऐसा भी होगा, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य चार स्थायी सदस्यों के नेताओं ने, महज़ छह महीने के भीतर चीन का दौरा किया होगा। फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 3 से 5 दिसंबर, 2025 तक चीन की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा की थी, जिसके बाद जनवरी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वहां पहुंचे थे। 20 मई को, बीजिंग में चीन-रूस रिश्तों के विकास में एक और अहम पल देखने को मिला। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ़ द पीपल में दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, जिसमें दोनों पक्ष चीन-रूस ट्रीटी ऑफ़ गुड-नेबरलिनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन को और बढ़ाने पर सहमत हुए।

बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक ज्वाइंट प्रेस मीटिंग में, राष्ट्रपति शी ने चीन-रूस रिश्तों के चार पहलुओं में बेहतर क्वालिटी के विकास को बढ़ावा देने की कोशिशों की बात कही : पहला, शी ने बेहतर क्वालिटी के राजनीतिक आपसी भरोसे को मज़बूत करने और एक-दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट को मज़बूत करने की कोशिशों की बात कही; दूसरा, शी ने चीन और रूस को बेहतर क्वालिटी के आपसी फ़ायदे वाले सहयोग को मज़बूत करने और मिलकर अपने-अपने विकास और फिर से ज़िंदा होने को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया; तीसरा, शी ने बेहतर क्वालिटी के लोगों के बीच लेन-देन को बढ़ावा देने और दोनों लोगों के बीच पीढ़ियों तक चलने वाली दोस्ती की नींव को मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया; और चौथा, शी ने चीन और रूस से बेहतर क्वालिटी के इंटरनेशनल तालमेल को आगे बढ़ाने और ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। ये चार पहलू साफ़ तौर पर चीन-रूस रिश्तों के बेहतर विकास के लिए एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाते हैं।

दोनों राष्ट्राध्यक्षों बड़े स्ट्रेटेजिक तालमेल को और बढ़ाने और सहयोग को गहरा करने के वास्ते साझा बयान पर साइन किए, और कई ज़रूरी द्विपक्षीय सहयोग डॉक्यूमेंट्स को पूरा होते देखा।

अभियान

नौतपा का तप और सूर्य कृपा, जब भक्ति से भर जाता है जीवन

सनातन धर्म में प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन को केवल मौसम का बदलाव नहीं माना गया, बल्कि उसे ईश्वर की दिव्य लीला और आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखा गया है। वर्ष का हर मास, हर ऋतु और हर विशेष कालखंड अपने भीतर कोई न कोई संदेश लेकर आता है। ज्येष्ठ मास में आने वाला नौतपा भी ऐसा ही एक पवित्र समय माना जाता है। जब सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणों से धरती को तपाते हैं, तब केवल वातावरण ही गर्म नहीं होता, बल्कि यह समय मनुष्य के भीतर छिपे आलस्य, नकारात्मकता और अव्यवस्था को भी जलाकर शुद्ध करने का अवसर बन जाता है। ऋषि-मुनियों ने नौतपा को केवल गर्मी के नौ दिन नहीं कहा, बल्कि इसे तपस्या, संयम, सेवा और भक्ति का महापर्व माना है। मान्यता है कि इन दिनों में किया गया जप, दान, पूजा और सेवा कई गुना फल प्रदान करती है और घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलती है।

भारतीय परंपरा में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। वे ऐसे देव हैं जिन्हें मनुष्य प्रतिदिन अपनी आंखों से देख सकता है। सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि जीवन, ऊर्जा, आत्मविश्वास और चेतना भी प्रदान करते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के पूरी सृष्टि को समान रूप से प्रकाश देते हैं। यही कारण है कि नौतपा के दौरान सूर्य उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य अपनी सबसे प्रखर अवस्था में होते हैं, तब उनकी ऊर्जा भी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव की आराधना करता है, उसके जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दिनों में घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में जल से भरा पात्र रखना अत्यंत शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को देवताओं का स्थान कहा गया है। यह दिशा ज्ञान, आध्यात्मिकता और दिव्य ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। जब इस दिशा में मिट्टी का घड़ा, तांबे का कलश या स्वच्छ जल से भरा पात्र रखा जाता है, तो माना जाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। यदि उस जल में तुलसी दल, गुलाब की पंखुड़ियां या चंदन की कुछ बूंदें डाल दी जाएं, तो वातावरण और भी सात्विक हो जाता है। यह केवल एक धार्मिक उपाय नहीं, बल्कि मन और वातावरण को शांत करने का माध्यम भी है।

भक्ति में भावना का महत्व सबसे अधिक होता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से जल का पात्र रखते हुए भगवान से केवल इतना कह दे कि “हे प्रभु, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखना,” तो उसकी प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर भव्यता नहीं, बल्कि सच्चे मन की सरलता देखते हैं। यही कारण है कि छोटे-छोटे उपाय भी जब श्रद्धा से किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव जीवन में गहराई से दिखाई देता है।

नौतपा के दिनों में प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा भी अत्यंत पवित्र मानी गई है। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले स्नान करके तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य को अर्पित करने से व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। जब जल की धारा से होकर सूर्य की किरणें आंखों तक पहुंचती हैं, तो मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। इसलिए उनकी उपासना से आत्मबल मजबूत होता है और मनुष्य के भीतर छिपी निराशा धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है।

पुराने समय में लोग नौतपा को सेवा और दया का पर्व मानते थे। गांवों में जगह-जगह प्याऊ लगाई जाती थीं। राहगीरों के लिए मिट्टी के घड़ों में ठंडा पानी रखा जाता था। लोग पक्षियों के लिए छतों पर जल के पात्र रखते थे। यह केवल सामाजिक परंपरा नहीं थी, बल्कि इसे ईश्वर सेवा माना जाता था। शास्त्रों में कहा गया है कि नौतपा में प्यासे को जल पिलाने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब पूरी प्रकृति तप रही होती है, तब किसी की प्यास बुझाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आज के समय में भी यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में गरीबों, मजदूरों, पशु-पक्षियों या राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करता है, तो वह वास्तव में धर्म का पालन करता है। ईश्वर मंदिरों में चढ़ाए गए महंगे प्रसाद से उतने प्रसन्न नहीं होते, जितने किसी प्यासे को पानी पिलाने से होते हैं। भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में भी बसती है। यही नौतपा का सबसे बड़ा संदेश है।

नौतपा आत्मअनुशासन का भी समय माना गया है। इन दिनों में सात्विक भोजन, संयमित व्यवहार और मन की पवित्रता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन नौ दिनों में क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, उसके जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है। मनुष्य के भीतर जो अशांति और तनाव होता है, उसका सबसे बड़ा कारण उसका असंयमित मन ही होता है। इसलिए ऋषियों ने इन दिनों को आत्मशुद्धि का अवसर बताया है।

घर में साफ-सफाई रखना भी इन दिनों अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से मुख्य द्वार के आसपास गंदगी, टूटे सामान और अव्यवस्था को नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना गया है। जहां स्वच्छता होती है, वहां देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। पुराने लोग कहते थे कि घर केवल ईंट-पत्थर से नहीं बनता, बल्कि उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा ही उसे वास्तविक गृह बनाती है। यदि घर में नियमित दीपक जले, भगवान का स्मरण हो और वातावरण में प्रेम बना रहे, तो वहां सुख-समृद्धि अपने आप आने लगती है।

तुलसी का पौधा भी नौतपा के दिनों में विशेष महत्व रखता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि प्रतिदिन सुबह-शाम तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी के आसपास का वातावरण शुद्ध और सात्विक माना जाता है। कई लोग नौतपा में शाम के समय घी का दीपक जलाकर सूर्य देव और भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ऐसा करने से घर में रोग, भय और नकारात्मकता का प्रभाव कम होने की मान्यता है। नौतपा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिन समय हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे सूर्य की तीव्र गर्मी के बाद वर्षा आती है और धरती फिर से हरी-भरी हो जाती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में आने वाले संघर्ष भी अंततः उसे मजबूत बनाते हैं। तप के बिना शुद्धि संभव नहीं। सोना भी अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अधिक मजबूत और परिपक्व बनता है।

भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि मन की निर्मलता है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरा हो, तो बड़े-बड़े अनुष्ठान भी अधूरे रह जाते हैं। लेकिन यदि मन में करुणा, दया और प्रेम हो, तो छोटा-सा दीपक भी ईश्वर तक पहुंच जाता है। नौतपा हमें यही सिखाता है कि बाहरी गर्मी के बीच भी भीतर की शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जब संसार तप रहा हो, तब मनुष्य को अपने भीतर प्रेम और सेवा का जल जीवित रखना चाहिए।

आज आधुनिक जीवन में लोग सुख और समृद्धि पाने के लिए अनेक उपाय करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय सदाचार और भक्ति है। जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, जहां बड़ों का सम्मान होता है, जहां जरूरतमंदों की सहायता की जाती है और जहां भोजन से पहले ईश्वर को याद किया जाता है, वहां कभी दरिद्रता स्थायी रूप से नहीं टिकती। नौतपा के दौरान किए गए छोटे-छोटे शुभ कार्य पूरे वर्ष जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक माने गए हैं। कहा जाता है कि ईश्वर बड़े यज्ञों और भव्य आयोजनों से अधिक प्रसन्न सच्चे मन से किए गए छोटे कार्यों से होते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से एक दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करे, किसी प्यासे को पानी पिला दे, किसी भूखे को भोजन करा दे या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे दे, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। नौतपा का संदेश भी यही है कि तप के बीच करुणा को जीवित रखा जाए।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गिर सोमनाथ के बाद गुजरात में 7 और स्थानों पर लगाए जाएंगे 'स्टैटकॉम'

- 'स्मार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर' के रूप में जाना जाने वाला यह सिस्टम ग्रिड में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या को दूर करता है
- 'गेटको' भारत में 'स्टैटकॉम' टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी
- 'स्टैटकॉम' से कृषि क्षेत्र में वोल्टेज स्थिरता और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई

गांधीनगर : एक समय बिजली की कमी वाला गुजरात राज्य आज देश में ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी और आत्मनिर्भर राज्य बन गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विद्युत क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधार के परिणास्वरूप राज्य में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुई। उनके नेतृत्व में ही गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए ज्योतिग्राम योजना शुरू की गई, जो अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन गई है। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात विद्युत क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने गिर सोमनाथ जिले के टिंबड़ी सबस्टेशन में राज्य का पहला अत्याधुनिक 'स्टैटिक सिंक्रोनस कम्पेनसेटर' (STATCOM - स्टैटकॉम) स्थापित करके पावर ग्रिड को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। आने वाले समय में राज्य के 7 महत्वपूर्ण सबस्टेशनों पर भी स्टैटकॉम लगाने की योजना है।

गुजरात का पहला स्टैटकॉम गिर सोमनाथ जिले में

गुजरात सरकार के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के अंतर्गत कार्यरत गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GETCO – गेटको) द्वारा अद्यतन स्टैटिक सिंक्रोनस कम्पेनसेटर स्थापित किया गया है। 'स्मार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर' के रूप में जाना जाने वाला यह सिस्टम ग्रिड में वोल्टेज स्थिरता और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही ग्रिड में किसी भी बदलाव की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया भी देता है।

5 मार्च, 2019 को गिर सोमनाथ जिले के 220 केवी टिंबड़ी सबस्टेशन में 120 एमवीएआर (मेगा वोल्ट एम्पीयर रिऐक्टिव) क्षमता वाला स्टैटकॉम कार्यरत हुआ। इसके साथ ही, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गेटको) भारत में स्टैटकॉम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी बन गई है।

क्यों पड़ी स्टैटकॉम की जरूरत?

गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग अधिक रहती है, जिससे ग्रिड में वोल्टेज की स्थिरता और बिजली की गुणवत्ता को बनाए रखना एक चुनौती बन जाती है। परंपरागत कैपेसिटर और रिएक्टर जैसी व्यवस्थाएं स्थिर सपोर्ट तो देती हैं, लेकिन मांग में होने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए एक विशेष सिस्टम की जरूरत थी। टिंबड़ी सबस्टेशन में सिंगल-सर्किट लिंक और आसपास विद्युत उत्पादन स्रोत के अभाव के कारण वोल्टेज में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता था। विशेषकर कृषि में बिजली की अधिक मांग होने के कारण वोल्टेज का स्तर 190 केवी से 245 केवी के बीच रहता था। पीक समय के दौरान वोल्टेज 190-200 केवी तक गिर जाता था। वहीं, मानसून के दौरान जब मांग कम होती है, तब 235-245 केवी तक बढ़ जाता था। इस परिस्थिति में वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए ऐसा डायनामिक सिस्टम शुरू किया गया, जो वोल्टेज स्थिरता और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

स्टैटकॉम ग्रिड की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह आवश्यकतानुसार रिएक्टिव पावर प्रदान या अवशोषित करके वोल्टेज को स्थिर रखता है। रियल-टाइम में काम करने वाला यह सिस्टम अलग-अलग लोड पर भी ग्रिड को संतुलित रखता है, पावर फैक्टर को नियंत्रित करता है, ओवर-वोल्टेज कम करता है और वोल्टेज के अचानक गिरने की स्थिति को रोकता है। इससे ट्रांसमिशन सिस्टम पर दबाव कम हुआ है, बिजली का नुकसान कम हुआ है और उपकरणों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। इस सिस्टम से गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली और आसपास के क्षेत्रों में विशेषकर किसानों को लाभ हुआ है। इसके साथ ही, ग्रामीण और औद्योगिक, दोनों प्रकार की जरूरतों के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

टिंबड़ी में मिली सफलता के बाद गुजरात सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी स्टैटकॉम स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत छह मौजूदा 220 केवी सबस्टेशनों- थराद, दियोदर, सागपरा, खेरालु, कुकमा और ध्रांगध्रा और आगामी 400 केवी धोलेरा-2 सबस्टेशन में 125 एमवीएआर क्षमता वाले स्टैटकॉम स्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह पहल राज्य के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करेगी और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

पश्चिम रेलवे मुख्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), मुंबई की वर्ष 2026 की प्रथम छमाही बैठक 21 मई, 2026 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान नराकास, मुंबई द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के 20 विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभाने वाले 7 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही, वर्ष 2025-26 में राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन सदस्य कार्यालयों – मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल; निदेशक, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, महालक्ष्मी, मुंबई; तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, लोअर परेल, मुंबई – को राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर नराकास, मुंबई की गृह पत्रिका 'राजभाषा प्रवाह' का भी अध्यक्ष महोदय द्वारा विमोचन किया गया।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में पश्चिम रेलवे हमेशा से अग्रणी रहा है। इसकी सार्थकता को देखते हुए पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक श्री के. पद्मनाथन द्वारा लिखित काव्य-संग्रह 'रुक जाना नहीं.....' का विमोचन भी बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक महोदय द्वारा किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने पुरस्कृत सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दीं और समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा के प्रचार-प्रसार और प्रयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना एक राष्ट्रीय कार्य है, क्योंकि भारत की आम जनता हिंदी को अच्छी तरह समझती है और इसका प्रयोग करती है। भारतीय संविधान निर्माता यह अच्छी तरह जानते थे कि भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की संवाहिका होती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी को 'राजभाषा' के रूप में स्वीकार किया गया है। कार्यालय प्रमुख स्वयं हिंदी में कार्य करेंगे तो स्वतः ही राजभाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा और अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने सभी कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालय की वेबसाइट निश्चित रूप से चेक करें। राजभाषा नियमानुसार वे द्विभाषी में होनी चाहिए और समय-समय पर जो सामग्री उनमें अपलोड की जाती हैं, वे भी द्विभाषी में हों और कार्यालय की वेबसाइट डिफॉल्ट रुप से हिंदी में ही खुले।

बैठक के प्रारंभ में पश्चिम रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी विनीत गुप्ता ने अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वास्तव में किसी भी समाज, राष्ट्र और सभ्यता की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। हिंदी भारत की विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं, भाषाओं, विधाओं और सम्प्रदायों को एक कड़ी में जोड़ती है। हिंदी ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज भी संपर्क भाषा के रुप में आम जनता के आपसी विचारों के आदान-प्रदान में विशेष योगदान दे रही है।

इस बैठक में मुंबई स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में अक्टूबर-2025 से मार्च-2025 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में समिति के सभी सदस्य कार्यालयों में अक्टूबर-2025 से मार्च-2025 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति संबंधी आंकड़ों को समिति की सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और कार्यालयों में राजभाषा को लागू करने के लिए कई सार्थक एवं नीतिगत निर्णय लिये गये।

बैठक में प्रधान कार्यालय-मध्य रेल, मुंबई सेंट्रल मंडल-पश्चिम रेलवे, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग (लेखा व हकदारी), मुंबई, प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (नौवहन), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बेलापुर आदि केंद्र सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक का संचालन एवं समापन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुनीता अहिरे के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

पश्चिम रेलवे मुंबई एवं गोरखपुर के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य मुंबई एवं गोरखपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर स्पेशल रविवार, 24 मई, 2026 को 00:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 17:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर – बोरीवली स्पेशल सोमवार, 25 मई, 2026 को 20:30 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करेगी तथा बुधवार को 11:30 बजे बोरीवली पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09157/09158 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर-बोरीवली स्पेशल मार्ग में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बरेली सिटी, इज्जतनगर, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती एवं खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में शयनयान एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09157 के विस्तारित फेरों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा IRCTC वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव समय एवं रेक संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की वर्चुअल उपस्थिति में कच्छ को नई दिल्ली से जोड़ने वाली सीधी रेल सेवा का शुभारंभ हुआ

- केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भुज-दिल्ली ट्रेन के प्रस्थान में राजस्थान के पाली से वर्चुअल माध्यम द्वारा सहभागी हुए
- भारतीय रेलवे परिवहन की महत्वपूर्ण कड़ी है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह वर्षों में इसका बड़े पैमाने पर कायाकल्प हुआ है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने आधुनिक रेलवे क्रांति में लीड ली है
- देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम पूरे जोश में चल रहा है
- 2014 के बाद गुजरात में 2900 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण हुआ
- 2026-27 में रेलवे बजट में गुजरात को 17366 करोड़ रुपए मिले

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की गांधीनगर से तथा केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की राजस्थान के पाली से वर्चुअल उपस्थिति में शुक्रवार को भुज से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन का प्रारंभ हुआ।

मुख्यमंत्री ने कच्छ को नई दिल्ली से जोड़ने वाली सीधी रेल सेवा की भेंट तथा हाल ही में अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट की मंजूरी की भेंट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेल परिवहन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में पिछले बारह वर्षों में बड़े पैमाने पर रेलवे का कायाकल्प हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात ने इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से आधुनिक रेलवे क्रांति में लीड ली है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 348 किलोमीटर गुजरात की धरती पर निर्मित हो रहा है।

उन्होंने गुजरात में रेलवे नेटवर्क के विकास की गति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और अधिक गतिशील बनी है, इसकी विस्तृत भूमिका प्रस्तुत की।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद राज्य में 2900 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण हुआ है। इसके अलावा राज्य में 1 लाख 28 हजार करोड़ रुपए के विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट कार्यरत हैं।

उन्होंने जोड़ा कि 2014 की तुलना में इस वर्ष 29 प्रतिशत अधिक राशि अर्थात 17366 करोड़ रुपए की राशि गुजरात को रेलवे बजट के अंतर्गत आवंटित की गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को पांच वंदे भारत, एक अमृत भारत और एक नमो भारत ट्रेन की भेंट देने के साथ विश्व के अग्रणी पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रियों को आसानी से पहुंचाने के लिए एकता नगर को रेलवे सेवाओं की कनेक्टिविटी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और रेल मंत्री के मार्गदर्शन में आजादी का यह अमृतकाल रेलवे को नई गति देने वाला और विकसित भारत के निर्माण का काल बनेगा। भुज-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को भुज रेलवे स्टेशन से रवाना करने के इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा, सांसद श्री विनोदभाई चावडा, कच्छ जिले के विधायक, पदाधिकारी, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तथा नागरिक उत्साहपूर्वक सहभागी हुए।

रूसी संघ के मुंबई स्थित महावाणिज्य दूत श्री इवान फेतिसोव ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

- गुजरात के साथ मैरीटाइम, शिप बिल्डिंग तथा एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में सहभागिता के लिए तत्परता दर्शाई
- मुख्यमंत्री को रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाली बिजनेस समिट में सहभागी होने का आमंत्रण दिया
- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का निमंत्रण दिया

गांधीनगर : रूसी संघ के मुंबई स्थित महावाणिज्य दूत श्री इवान फेतिसोव ने शुक्रवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री के साथ आयोजित इस बैठक में रूसी महावाणिज्य दूत ने गुजरात के साथ विशेषकर मैरीटाइम, शिप बिल्डिंग तथा एजुकेशन सेक्टर्स में सहभागिता एवं समन्वय के लिए तत्परता दर्शाई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पृष्ठभूमि दी कि गुजरात के पास देश में सबसे विशाल समुद्री तट है और गुजरात ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-दर्शन में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की नई परंपरा विकसित की है। श्री पटेल ने विचार-विमर्श के दौरान यह भी कहा कि देश की 40 प्रतिशत कारगो हैंडलिंग गुजरात के बंदरगाहों से होती है।

मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इतना ही नहीं; शिप रिसाइकलिंग तथा शिप बिल्डिंग में भी गुजरात ने अग्रसरता प्राप्त की है और गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटियों से गुजरात मॉडर्न एजुकेशन हब बनने के लिए सज्ज है।

रूसी संघ के महावाणिज्य दूत श्री इवान ने उल्लेख किया कि रूस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पार्टनर कंट्री रहा था और हाल ही में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टनर ऑर्गेनाइजर के रूप में सहभागी हुआ था।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आगामी समय में आयोजित होने वाली बिजनेस समिट में भाग लेने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री ने भी वाइब्रेंट समिट की आगामी कड़ी में रूस के प्रतिनिधिमंडल को सहभागी होने का निमंत्रण दिया।

इस शिष्टाचार भेंट तथा बैठक में उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) की प्रबंध निदेशक श्री प्रवीणा डी. के. तथा इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो (इंडेक्स्ट-बी) के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री अमित प्रकाश यादव भी सहभागी हुए।

फियो ने वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल की कनाडा यात्रा का स्वागत किया; भारत-कनाडा सीईपीए वार्ता के लिए सकारात्मक प्रगति की संभावना व्यक्त की

नई दिल्ली, 22 मई, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की 25-27 मई, 2026 तक कनाडा की आगामी यात्रा का स्वागत किया है। फियो इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। यह यात्रा ऐसे समय में विशेष महत्व रखती है जब भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत को फिर से शुरू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसका एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस.सी. रल्हन ने कहा कि फियो माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की कनाडा यात्रा का पुरजोर स्वागत करता है। यह यात्रा आर्थिक जुड़ाव को फिर से बनाने और प्रस्तावित सीईपीए पर चर्चा को तेज करने के लिए दोनों राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत और कनाडा कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में एक-दूसरे के पूरक हैं, जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं।

श्री रल्हन ने आगे कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौता भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए नए अवसर खोलेगा। यह बाजार तक पहुंच में सुधार करके, व्यापार प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार-संचालित क्षेत्रों में अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करके ऐसा करेगा। बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्संरेखण के बीच, भारत-कनाडा के मजबूत व्यापारिक संबंध दोनों देशों के लिए आर्थिक लचीलेपन और विकास में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।

फियो ने उल्लेख किया कि भारत और कनाडा के बीच यह नया जुड़ाव एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है जब वैश्विक बाजार भू-राजनीतिक संघर्षों, टैरिफ-संबंधी व्यवधानों और बदलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार गठबंधनों से उत्पन्न अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि बढ़ा हुआ द्विपक्षीय सहयोग व्यापारिक साझेदारियों के विविधीकरण का समर्थन करेगा और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को मजबूत करेगा।

शीर्ष निर्यातक निकाय ने दोनों देशों के बीच मंत्री-स्तरीय आदान-प्रदान और व्यापार मिशनों में बढ़ती गति को भी रेखांकित किया, जिसमें भारतीय और कनाडाई व्यापार अधिकारियों के बीच हालिया जुड़ाव भी शामिल हैं। फियो का मानना है कि निरंतर संवाद और उद्योग-स्तरीय सहयोग विश्वास बहाल करने और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फेडरेशन ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री की यात्रा सीईपीए वार्ताओं को नई गति प्रदान करेगी और भारत तथा कनाडा के बीच गहन आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

कच्छ से देश की राजधानी दिल्ली के लिए नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाई हरी झंडी

रेल यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए तथा कच्छ क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से सीधे एवं बेहतर रेल संपर्क प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज दिनांक 22 मई, 2026 को भुज एवं दिल्ली के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। गाड़ी संख्या 19403/19404 भुज–दिल्ली–भुज एक्सप्रेस का उद्घाटन माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया गया।

इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज़ादी के बाद से भुज–जालोर–पाली क्षेत्र को दिल्ली के साथ सीधी रेल कनेक्टिविटी देने का सपना आज साकार हुआ है। उन्होंने बताया कि देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है, जिसके अंतर्गत गुजरात में 4600 करोड़ रुपये के निवेश से 85 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिनमें से 15 स्टेशनों का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 24 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है तथा 14,000 करोड़ रुपये के निवेश से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का कार्य भी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि तारंगा हिल–अंबाजी रेल लाइन का कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर है तथा इसका पहला खंड दिसंबर माह में प्रारंभ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भुज–बरेली साप्ताहिक ट्रेन सेवा संचालित की जा रही है, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत यात्री बरेली एवं उत्तर भारत क्षेत्र के होते हैं। नई भुज–दिल्ली एक्सप्रेस के प्रतिदिन संचालन से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, नियमित एवं बेहतर रेल सेवा उपलब्ध होगी।

माननीय रेल मंत्री ने आगे कहा कि नई भुज–दिल्ली एक्सप्रेस से गुजरात के 6 शहरों तथा अन्य 19 शहरों को दिल्ली से सीधी रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इस ट्रेन सेवा से विद्यार्थियों, श्रमिकों, हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े कारीगरों, व्यापारियों, उद्योग जगत एवं किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रणोत्सव के दौरान दिल्ली एवं उत्तर भारत के यात्रियों को कच्छ आने के लिए प्रतिदिन सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल का अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है। उन्होंने बताया कि हाल ही में अहमदाबाद–धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की सौगात भी गुजरात को मिली है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत निर्मित वंदे भारत एवं नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों ने न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की है, बल्कि देश के विकास को भी नई गति दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कार्य गुजरात में तीव्र गति से चल रहा है तथा 508 किलोमीटर लंबी परियोजना में से 348 किलोमीटर का निर्माण गुजरात में हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के बजट में गुजरात को रिकॉर्ड 17,366 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2014 की तुलना में लगभग 29 गुना अधिक है। वर्तमान में गुजरात राज्य में 1,28,748 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 12 वर्षों में गुजरात के सभी रेलवे मार्गों का 100% विद्युतीकरण किया गया है।

इस अवसर पर भुज स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में श्री त्रिकमभाई छांगा, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, गुजरात सरकार एवं माननीय विधायक – अंजार, माननीय सांसद (कच्छ) श्री विनोद एल. चावड़ा, माननीय विधायक (भुज) श्री केशुभाई शिवदास पटेल, श्री प्रद्युम्नसिंह जाडेजा, माननीय विधायक – अबडासा, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

नई दैनिक ट्रेन सेवा के शुभारंभ से कच्छ क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो गई है। यह ट्रेन गुजरात एवं राजस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों एवं स्टेशनों को जोड़ते हुए यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करेगी।

गाड़ी संख्या 19403/19404 भुज–दिल्ली–भुज एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 19403 भुज–दिल्ली एक्सप्रेस 23 मई 2026 से प्रतिदिन भुज से 11:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 19404 दिल्ली–भुज एक्सप्रेस 24 मई 2026 से प्रतिदिन दिल्ली से 16:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 19:35 बजे भुज पहुंचेगी।

मार्ग में प्रमुख ठहराव

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूणी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर एवं रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में 2-टियर एसी, 3-टियर एसी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भुज से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन सेवा प्रारंभ करने की मांग भी रखी गई, जिस पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने सकारात्मक विचार करने एवं आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

भावनगर मंडल की तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें अब नियमित रूप से चलेंगी

यात्रियों की सुविधा, उनकी बढ़ती मांग एवं ट्रेनों को मिल रहे उत्कृष्ट प्रतिसाद को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल की तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को अब जून, 2026 से नियमित ट्रेनों के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं प्रयासों से संभव हुआ है।

इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रेनों के नियमित संचालन से यात्रियों को पूर्व नियोजन में सुविधा होगी तथा किराए में कमी के कारण किफायती यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

ट्रेन नंबर 09529/09530 धोला-भावनगर टर्मिनस दैनिक स्पेशल अब ट्रेन नंबर 59239/59240 धोला-भावनगर दैनिक पैसेन्जर के रूप में चलेगी। ट्रेन नंबर 59239 धोला-भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर धोला स्टेशन से 11.30 बजे प्रस्थान कर 12.50 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 59240 भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर भावनगर टर्मिनस से 13.15 बजे प्रस्थान कर 14.35 बजे धोला पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में सणोसरा, बजुड, सोनगढ़, सिहोर (गुजरात), खोडीयार मंदिर, वरतेज एवं भावनगर परा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी। इन दोनों ट्रेनों के लिए यह परिवर्तन 01 जून 2026 से प्रभावी होगा।

ट्रेन नंबर 09215/09216 गांधीग्राम-भावनगर टर्मिनस दैनिक स्पेशल अब ट्रेन नंबर 59231/59232 गांधीग्राम-भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर के रूप में चलेगी। ट्रेन नंबर 59231 गांधीग्राम-भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर गांधीग्राम से 06.35 बजे प्रस्थान कर 11.25 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। यह परिवर्तन 02.06.2026 से प्रभावी होगा। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 59232 भावनगर टर्मिनस-गांधीग्राम दैनिक पैसेन्जर भावनगर टर्मिनस से 17.00 बजे प्रस्थान कर 21.55 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। यह परिवर्तन 01.06.2026 से प्रभावी होगा। यह ट्रेन मार्ग में वस्त्रापुर, सरखेज, बावला, धोलका, धंधुका, बोटाद, धोला, सिहोर (गुजरात) एवं भावनगर परा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी। ट्रेन नंबर 09211/09212 गांधीग्राम-बोटाद दैनिक स्पेशल अब ट्रेन नंबर 59237/59238 गांधीग्राम-बोटाद दैनिक पैसेन्जर के रूप में चलेगी। ट्रेन नंबर 59237 गांधीग्राम-बोटाद दैनिक पैसेन्जर गांधीग्राम से 09.15 बजे प्रस्थान कर 13.30 बजे बोटाद पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 59238 बोटाद-गांधीग्राम दैनिक पैसेन्जर बोटाद से 14.05 बजे प्रस्थान कर 18.05 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में वस्त्रापुर, सरखेज, मोरैया, मटोडा, बावला, धोलका, गोधनेश्वर, कोठ गांगड, अरणेज, लोथल भुरखी, लोलीया, हडाला भाल, धोली भाल, रायका, धंधुका, तगडी, भीमनाथ, चंदरवा, जालिला रोड, सारंगपुर रोड एवं अलाऊ स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी। इन दोनों ट्रेनों के लिए यह परिवर्तन 01.06.2026 से प्रभावी होगा। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि यह निर्णय यात्रियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे उन्हें नियमित, सुलभ एवं किफायती रेल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

पश्चिम रेलवे – रतलाम

ई –निविदा सूचना

संख्या : W/623/5/1/NIT. दिनांक : 20/05/2026, मंडल रेल प्रबंधक /मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम, निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई–निविदा के माध्यम से वेबसाईट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है। **ई–टेंडरिंग** : RTM-2026-27-34, **कार्य का नाम** : RTM-DADN सेक्शन विभिन्न स्टेशनों पर (RTM, LMNR, DADN और IND को छोड़कर) वर्ष 2026–2029 के लिए तीन वर्षों तक पीने योग्य पानी की आपूर्ति। **अनुमानित मात्रा** : टेंडर के अनुसार, **अनुमानित लागत** : ₹1,04,44,124.25/–, **बयाना राशि** : ₹2,08,900/– **कार्य समापन अवधि** : 36 महीने। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कार्य, **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि** : 20/05/2026, **निविदा खुलने की तिथि** : 15/06/2026 • विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। SNP-069

हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

VGRC का अगला पड़ाव होगा वड़ोदरा: मध्य गुजरात बनेगा औद्योगिक और पर्यटन विकास का नया ग्लोबल हब

- जून 2026 के अंतिम सप्ताह में वड़ोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) के 'मध्य गुजरात' संस्करण का होगा भव्य आयोजन
- राज्य के कुल विनिर्माण में 28% का योगदान देने वाले इस क्षेत्र ने 20.54 बिलियन डॉलर का किया है निर्यात
- इस सम्मेलन में सेमीकंडक्टर और फिनटेक जैसे आधुनिक उद्योगों के साथ-साथ पर्यटन विकास पर रहेगा विशेष फोकस
- मेहसाणा, राजकोट और सूरत संस्करणों में मिले ऐतिहासिक निवेश के बाद अब वड़ोदरा से नए रिकॉर्ड की है उम्मीद

गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की ऐतिहासिक सफलता और विरासत को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार अब क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी में है। इसी विज़न के तहत वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का अगला भव्य आयोजन जून 2026 के अंतिम सप्ताह में वड़ोदरा में होने जा रहा है, जो मुख्य रूप से 'मध्य गुजरात' क्षेत्र पर केंद्रित होगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, वड़ोदरा, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, छोटाउदेपुर, नर्मदा और महीसागर सहित 10 जिलों वाला यह क्षेत्र, राज्य के कुल विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) उत्पादन में 28% की मजबूत हिस्सेदारी रखता है।

औद्योगिक उत्पादन का पावरहाउस: विनिर्माण में मध्य गुजरात का दबदबा

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (2022-23) के आधिकारिक जिला-स्तरीय आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में इस क्षेत्र का असाधारण दबदबा नजर आता है। राज्य के कुल 'अन्य परिवहन उपकरण' (जिसमें रेलवे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, विमान, अंतरिक्ष यान, दोपहिया और तिपहिया वाहन आदि शामिल हैं) के विनिर्माण उत्पादन में मध्य गुजरात का योगदान अकेले 93% है। इसके अलावा, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में 92%, पेय पदार्थों में 70%, तथा फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों प्रत्येक में 63% का भारी योगदान इसी क्षेत्र से आता है।

निवेशकों के लिए यह क्षेत्र इसलिए भी सबसे आदर्श गंतव्य है क्योंकि गुजरात का लगभग 62% कुल क्षेत्रफल दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इस कॉरिडोर की प्रगति को गति देने के लिए मध्य गुजरात में दो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स विकास के विभिन्न चरणों में तेजी से आकार ले रहे हैं जिसमें 5,560 एकड़ में फैला धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेन्ट रीजन (DSIR) और 2,849 एकड़ का मांडल-बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेन्ट रीजन (MBSIR) शामिल हैं।

हर जिले की अपनी विशिष्ट पहचान: पेट्रोकेमिकल से लेकर फिनटेक तक

मध्य गुजरात की सबसे बड़ी ताकत इसकी जिलावार औद्योगिक विविधता और विशेषज्ञता है। वड़ोदरा का रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र जिले के कुल विनिर्माण उत्पादन का 61% हिस्सा संभालता है। वहीं, अहमदाबाद ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स (18%), टेक्सटाइल (15%), बेसिक मेटल्स (13%) और फार्मास्यूटिकल्स (9%) में अग्रणी है। गांधीनगर का विनिर्माण उत्पादन मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग (18%), बेसिक मेटल्स (17%) और रसायनों (14%) द्वारा संचालित है। इसके साथ ही राज्य की राजधानी अपने शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग और 'गिफ्ट सिटी' की उपस्थिति के माध्यम से क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का नेतृत्व करती है।

दूसरी ओर, आणंद का विनिर्माण आधार मुख्य रूप से एग्रो और डेयरी प्रोसेसिंग (50%) तथा रसायनों (12%) पर टिका है। पंचमहाल अपनी ताकत ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स (23%), रबर और प्लास्टिक (19%) तथा फार्मास्यूटिकल्स (15%) सेक्टर से प्राप्त करता है, जबकि खेड़ा रबर और प्लास्टिक उत्पादों (23%) तथा फूड प्रोसेसिंग (22%) द्वारा संचालित है। जनजातीय और ग्रामीण बेल्ट में, नर्मदा के उत्पादन में फूड प्रोसेसिंग (92%) का पूर्ण दबदबा है, जबकि छोटाउदेपुर एग्रो और फूड प्रोसेसिंग (56%) तथा दाहोद फूड प्रोसेसिंग (48%) के माध्यम से इस विकास यात्रा में अपनी ठोस भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।

ग्लोबल मार्केट में धमक: 20.54 बिलियन डॉलर का निर्यात

मध्य गुजरात की व्यावसायिक पहुँच अब दुनिया के नक्शे पर 219 से अधिक देशों तक फैल चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का कुल निर्यात 20.54 बिलियन डॉलर के जादुई आंकड़े को छू गया। इस निर्यात बास्केट में 3.67 बिलियन डॉलर (17.8%) की हिस्सेदारी के साथ फार्मास्यूटिकल्स सबसे आगे रहा। इसके बाद परमाणु रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी का योगदान 2.79 बिलियन डॉलर (13.6%), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण 1.79 बिलियन डॉलर (8.7%), सड़क वाहन और पुर्जे 1.47 बिलियन डॉलर (7%), ऑर्गेनिक केमिकल्स 1.45 बिलियन डॉलर (7%), और रंगाई, टैनिंग व कलरिंग मैटर 1.03 बिलियन डॉलर (5%) का स्थान रहा। वैश्विक बाजारों में अमेरिका (USA) मध्य गुजरात के उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है, जिसकी कुल निर्यात में 23.8% (4.88 बिलियन डॉलर) की हिस्सेदारी रही, जिसके बाद क्रमशः यूएई (7.3%), थाईलैंड (3%), यूके (2.8%), और सऊदी अरब (2.7%) का नंबर आता है।

भविष्य के सेक्टर्स और हेरिटेज टूरिज्म पर रहेगा विशेष फोकस

आगामी वीजीआरसी (मध्य गुजरात) में न केवल पारंपरिक उद्योगों, बल्कि भविष्य के हाई-टेक सेक्टर्स पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस सम्मेलन के फोकस क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस और रक्षा, फिनटेक, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र और परिधान, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, MSMEs, तथा पर्यटन और संस्कृति शामिल हैं।

इस सम्मेलन की एक और बड़ी विशेषता क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने के लिए 'पर्यटन और संस्कृति' को एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में पेश करना है। हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद के गांधी आश्रम, वड़ोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस, गांधीनगर के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर और पंचमहाल स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 'चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क' के जरिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की बड़ी रणनीति है। विरासत से परे, यह क्षेत्र नर्मदा की विश्व प्रसिद्ध 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी', नलसरोवर पक्षी अभयारण्य और पावागढ़ हिल कॉरिडोर के माध्यम से इको-टूरिज्म और अनुभवात्मक यात्रा जैसी पहलों को भी बढ़ावा दे रहा है। साथ ही, गांधीनगर का महात्मा मंदिर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की बदौलत यह क्षेत्र आकर्षक MICE यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसिंग और एग्जीबिशन पर्यटन का एक प्रमुख ग्लोबल हब बन रहा है।

VGRC बना निवेश का 'सुपरहिट' मॉडल: पिछले संस्करणों में टूटे कई रिकॉर्ड्स

VGRC का यह क्षेत्रीय फॉर्मेट निवेश जुटाने और वैश्विक भागीदारी का एक प्रामाणिक और बेहद सफल फॉर्मूला बन चुका है। 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्यों के अनुरूप आयोजित हुए पिछले तीनों संस्करणों ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस शृंखला की शुरुआत अक्टूबर 2025 में मेहसाणा में आयोजित उत्तर गुजरात के उद्घाटन संस्करण से हुई, जिसने 29,000 से अधिक पंजीकरणों और 80 से अधिक देशों के 440 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की ऐतिहासिक भागीदारी देखी, जिसके परिणामस्वरूप 3.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के साथ 1,264 एमओयू (MoUs) पर मुहर लगी। इसके बाद, जनवरी 2026 में राजकोट में आयोजित कच्छ और सौराष्ट्र संस्करण ने लगभग 29,000 पंजीकरणों और 57 देशों के करीब 400 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को आकर्षित किया, जिसके तहत 5.78 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश प्रस्तावों वाले 5,492 एमओयू का एक नया रिकॉर्ड बना। इसी सफल कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हाल ही में मई 2026 में सूरत में संपन्न दक्षिण गुजरात संस्करण ने भी 20,000 से अधिक पंजीकरणों और 27 देशों के 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ 3.53 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 2,792 एमओयू को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा। इन लगातार ऐतिहासिक सफलताओं के बाद, अब देश-विदेश के निवेशकों की निगाहें वड़ोदरा में होने वाले इस आगामी महामंथन पर टिकी हैं, जो मध्य गुजरात को वैश्विक पटल पर विकास के एक नए रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने जा रहा है।

मांग में अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल और गैस कंपनियों ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति जारी रखी है

पीआईबी अहमदाबाद द्वारा 22 मई 2026 को शाम 8:24 बजे प्रकाशित।

गुजरात राज्य स्तरीय समन्वयक (एसएलसी) ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) - इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल - राज्य और देश के कुछ क्षेत्रों में ईंधन की बढ़ती मांग के बीच पेट्रोल (एमएस), डीजल (एचएसडी) और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में परिचालन और लॉजिस्टिक्स समन्वय को लगातार बनाए रख रही हैं।

हाल के दिनों में, ओएमसी द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

एचएसडी (डीजल) – खुदरा बिक्री (1 से 21 मई)

राज्य	ज़िला	चालू वर्ष (सीवाई) मात्रा (किलोग्राम लीटर में)	पिछले वर्ष (LY) का आयतन (KL में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (% वृद्धि)
गुजरात	अहमदाबाद	44414	31990	39%
	आनंद	8717	5441	60%
	अरावली	7019	5227	34%
	बनासकांठा	23794	14383	65%
	गांधीनगर	11105	8330	33%
	खेड़ा	10098	7502	35%
	मेहसाणा	13426	8986	49%
	पाटन	6745	4765	42%
	साबरकांथा	8048	5284	52%
	वाव - थाराड		1306	918 42%
	अमरेली	8996	6630	36%
	भावनगर	12458	7828	59%
	नाव	3709	2071	79%
	देवभूमि द्वारका	7361	5502	34%
	गिर सोमनाथ	6177	3509	76%
	जामनगर	12104	8586	41%
	जूनागढ़	8924	5768	55%
	कच्छ	48378	27671	75%
	मोरबी	22354	18349	22%
	पोरबंदर	5327	3531	51%
	राजकोट	24367	15777	54%
	सुरेंद्रनगर	17746	12724	39%
	भरूच	19728	16635	19%
	छोटा उदेपुर	5389	3904	38%
	दाहोद	6247	4886	28%
	महासागर	2306	1754	31%
	नर्मदा	1941	1463	33%
	नवसारी	11568	9205	26%
	पंचमहल	7640	6511	17%
	सूरत	38172	29734	28%
	तापी	7653	5743	33%
	डैंग	727	502	45%
	वडोदरा	25440	17263	47%
	वलसाद	13342	12027	11%
	कुल गुजरात राज्य	452726	320399	41%

केंद्र शासित प्रदेश ज़िला चालू वर्ष (सीवाई) मात्रा (किलोग्राम लीटर में) पिछले वर्ष (LY) का आयतन (KL में) पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (% वृद्धि)

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली	7197	6097	18%
	दमन	2790	3389	21%
	कुल केंद्र शासित प्रदेश	11025	9211	20%

ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में जुताई और कटाई जैसी मौसमी गतिविधियों के कारण ईंधन की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अलावा निजी आपूर्तिकर्ताओं के बीच मूल्य अंतर के कारण उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा आउटलेट (पेट्रोल पंप) की ओर और संस्थागत / वाणिज्यिक ग्राहक खुदरा ईंधन आउटलेट की ओर रुख कर रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां अपने व्यापक राष्ट्रव्यापी टर्मिनल नेटवर्क, डिपो, पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और खुदरा दुकानों के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति बनाए रखती हैं। आपूर्ति दल, परिवहन नेटवर्क, टर्मिनल संचालन और चुनिंदा खुदरा दुकानें चौबीसों घंटे (24 घंटे) काम कर रही हैं ताकि उत्पादों की निर्बाध आवाजाही और बाजारों में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां ईंधन की निर्बाध आपूर्ति के लिए राज्य प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखती हैं।

तेल उद्योग उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सुचारू और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सामान्य खरीदारी जारी रखें और घबराकर खरीदारी न करें। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे ईंधन की उपलब्धता के संबंध में सटीक जानकारी के लिए केवल अधिकृत एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

(रिलीज़ आईडी: 2264342) आगंतुकों की संख्या: 40

यह विज्ञप्ति पढ़ें: अंग्रेज़ी

मुख्य न्यायाधीश के बयान के बाद शुरू हुई 'कोकरोच जनता पार्टी' ने 6 दिनों में सोशल मीडिया पर धूम मचा दी

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान के विरोध में शुरू किया गया 'कोकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)' नाम का डिजिटल अभियान महज 6 दिनों में इंटरनेट पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर इस पार्टी की खूब चर्चा हो रही है। कोकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट, जो महज 6 दिनों में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है, कल भाजपा के फॉलोअर्स की संख्या को भी पार कर गया।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द 'तिलचट्टा' को कुछ लोगों ने गंभीरता से ले लिया और एक ऑनलाइन अभियान शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्य न्यायाधीश के फॉलोअर्स की संख्या 1.6 लाख से बढ़कर 1.4 करोड़ हो गई है। वहीं, इंस्टाग्राम पर भाजपा के फॉलोअर्स की संख्या मात्र 88 लाख है। चूंकि यह डिजिटल व्यंग्य खतरनाक रूप ले रहा है, इसलिए भारत सरकार ने कल मुख्य न्यायाधीश के सोशल मीडिया अकाउंट्स को निलंबित कर दिया। अब जब आप X पर मुख्य न्यायाधीश का अकाउंट खोलते हैं, तो लिखा होता है, "कानूनी मांग के कारण यह अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया है।"

यह विचार कैसे आया?

अभिजीत ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मैं सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस का बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं की तुलना तिलचट्टों और परजीवियों से करते हुए व्यवस्था की आलोचना की थी। मैंने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि अगर सारे तिलचट्टे एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? मुझे जेनरेशन-जेड और 25 साल तक के युवाओं से चौंकाने वाले जवाब मिले। उन्होंने कहा कि हमें एक साथ आना चाहिए और एक मंच बनाना चाहिए। फिर मैंने तिलचट्टा जनता पार्टी (सीजेपी) का गठन किया।"

अभिजीत ने इस पार्टी की सदस्यता के लिए चार मानदंड भी प्रस्तुत किए हैं: बेरोजगारी, आलस्य, ऑनलाइन गपशप की लत और पेशेवर गुस्से को निकालने की क्षमता। उन्होंने इस पार्टी का लोगो भी डिजाइन किया है, जिसमें एक तिलचट्टा बना हुआ है।

इस प्रकार, सीजेपी का पुराना खाता ब्लॉक कर दिया गया और एक नया खाता बनाया गया, जिसका नाम था "कॉकरोच इज़ बैक", और उसके नीचे टैगलाइन थी: "कॉकरोच कभी नहीं मरते"। यह नया खाता यह संदेश देता है कि कॉकरोच कभी नहीं मरते।

सूरत नगर निगम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने दवा प्रतिपूर्ति प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ ने 18/05/2026 को सूरत नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। वर्तमान में, नगर निगम के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाहर से दवाइयां मंगाई जा रही थीं, जो अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थीं। ये दवाइयां मुफ्त में दी जा रही थीं। अब इस प्रथा को बंद कर दिया गया है और प्रतिपूर्ति प्रणाली शुरू कर दी गई है। यह प्रथा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों के खिलाफ है। इस प्रतिपूर्ति प्रणाली को बंद किया जाना चाहिए।

सूरत नगर निगम ने पुराने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी को पहले अपनी जेब से दवा खरीदनी होगी और तीन महीने बाद दवा का पैसा उनके वेतन में जमा कर दिया जाएगा। कुछ कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें हर महीने 10,000 से 15,000 रुपये की दवा मिल रही है। वे अपनी पेंशन पर मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और हर महीने इतना बड़ा खर्च वहन करना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए, पुरानी व्यवस्था ऐसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वरदान साबित हुई थी। हम नगर निगम द्वारा इस व्यवस्था को बंद करके कर्मचारियों को कुचलने के इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं।

हम मांग करते हैं कि सूरत नगर निगम इस परिपत्र को रद्द करे। इसके लिए 25/05/2026 को आवेदन दिया जाएगा। हालांकि, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम 10/06/2026 को दोपहर 3 बजे सूरत नगर निगम के मुख्यालय के द्वार के पास धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ ने सूरत नगर निगम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। आज भाई लाल बी. वैष्णव के मुख्यालय में कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न संघों के नेता सर्वश्री जयंतीभाई वाघेला, विजयभाई शेनमारे, शशिकांतभाई सोलंकी, मोहम्मद इकबाल शेख, किरीटभाई वाघेला, देवेंद्र प्रजापति और अन्य उपस्थित थे।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा 2372 रुपये और चांदी वायदा 16219 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा 8 रुपये नरम

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 15 से 21 मई के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2660263.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 331916.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 2328344.66 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 38654.45 करोड़ रुपये का हुआ।

आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 211105.05 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 160790 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160992 रुपये और नीचे में 157547 रुपये पर पहुंचकर, 161978 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2372 रुपये या 1.46 फीसदी लुढ़ककर 159606 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी मई वायदा सप्ताह के अंत में 2105 रुपये या 1.62 फीसदी गिरकर 127780 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मई वायदा 266 रुपये या 1.64 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 15999 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 160003 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160349 रुपये और नीचे में 157152 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 2448 रुपये या 1.52 फीसदी औंधकर 159005 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 159962 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160620 रुपये और नीचे में 157159 रुपये पर पहुंचकर, 161664 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2598 रुपये या 1.61 फीसदी गिरकर 159066 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सप्ताह के आरंभ में 280000 रुपये के भाव पर खूलकर, 283219 रुपये के उच्च और 264949 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 291102 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 16219 रुपये या 5.57 फीसदी की गिरावट के साथ 274883 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 14893 रुपये या 5.07 फीसदी घटकर 278588 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 14889 रुपये या 5.07 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 278594 रुपये प्रति किलो हुआ।

- कमोडिटी वायदाओं में 331916 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 2328344 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 211105 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार

मेटल वर्ग में 36013.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा सप्ताह के अंत में 40.4 रुपये या 2.92 फीसदी औंधकर 1345.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता मई वायदा सप्ताह के अंत में 5 पैसे या 0.01 फीसदी के सुधार के साथ 367.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 1.25 रुपये या 0.32 फीसदी बढ़कर सप्ताह के अंत में 386.75 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा मई वायदा सप्ताह के अंत में 40 पैसे या 0.2 फीसदी की नरमी के साथ 203.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 84786.45 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 9458 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 10150 रुपये के उच्च और 9211 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 8 रुपये या 0.09 फीसदी लुढ़ककर 9342 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 9 रुपये या 0.1 फीसदी गिरकर 9339 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 281 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 303.4 रुपये के उच्च और 277.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 12.7 रुपये या 4.58 फीसदी की मजबूती के साथ 290.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा सप्ताह के अंत में 12.7 रुपये या 4.58 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 290.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 994.5 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 9.2 रुपये या 0.93 फीसदी गिरकर 985.3 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 101427.67 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 109677.38 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 27598.50 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 4239.52 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 103.27 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 3951.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 54086.50 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 30600.96 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 10.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 5799 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 35596 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 6309 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 82823 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 17242 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9189 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19929 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 48953 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14227 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 12420 लोट के स्तर पर था।